



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2018/आश्विन 11, 1940

No. 367]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितंबर, 2018

सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार श्रीलंका और बंगलादेश के क्षेत्रीय जलमार्ग के माध्यम से एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन जाने वाले जलयानों तथा कार्गो के लिए रियायती तटीय प्रशुल्क के संबंध में एक सामान्य आदेश पारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी

इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एसोसिएशन

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितंबर, 2018 के 25 वें दिन पारित)

यह मामला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार श्रीलंका और बंगलादेश के क्षेत्रीय जलमार्ग के माध्यम से एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन जाने वाले जलयानों तथा कार्गो के लिए रियायती तटीय प्रशुल्क से संबंधित है जिसे इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) द्वारा ईमेल दिनांक 24 मई 2018 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2.1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं. पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1 जनवरी 2005 द्वारा जारी किए गए नीति निदेश और उसके बाद के नीति निदेश दिनांक 15 मार्च 2005 के अनुपालन में, तटीय रियायती पोत संबंधित प्रभार और तटीय रियायती कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभार प्रशुल्क आदेशों दिनांक 7 जनवरी 2005 और 15 मार्च 2005 द्वारा महापत्तन न्यासों और बीओटी परिचालकों के दरमानों में निर्धारित किए गए थे जोकि निम्नवत् हैं:-

- “1 सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
- 2.1 सभी तटीय कार्गो/कंटेनरों, ताप कोयला से इतर, कच्चा तेल सहित पीओएल, लौह अयस्क तथा लौह अयस्क गुट्टिकाओं के लिए कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
- 2.2 कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायती दरें घाटशुल्क सहित घाट से/को भंडारण यार्ड तक स्थानांतरण और जलयान तट स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर वसूल की जाएंगी।
- 2.3 कंटेनर संबंधित प्रभारों के मामले में, समोकेत बॉक्स दर पर रियायत लागू है। जहां मदवार प्रभार वसूल किए जाते हैं, वहां रियायत जलयान तटस्थानांतरण तथा घाट से/को भंडारण यार्ड तक स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रभारों एवं कार्गो तथा कंटेनरों पर घाटशुल्क पर होगी।
- 3 तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोतों के लिए प्रभार भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित और संग्रहीत किए जाएंगे।”

2.2. तत्पश्चात्, बीओटी परिचालकों में से एक अर्थात् वीओसीपीटी में परिचालन कर रहे दक्षिण भारत गेटवे टर्मिनल प्रा. लि. (डीबीजीटीपीएल) द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के संदर्भ में और इस मामले में जहाजरानी महानिदेशालय से उसके पत्र सं. सीडी-12/विविध (17)/14 दिनांक 13/17 अगस्त 2015 द्वारा प्राप्त पत्र सं. एसडी-12/विविध (17)/14 दिनांक 19 नवंबर 2015 और पत्र सं. एसडी-9/चार्ट(309)/2016 दिनांक 20 मई 2016 के आधार पर, वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर कार्यवाही करते समय, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 और संशोधन आदेश सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 10 जून 2016 द्वारा, उपर्युक्त पैरा 2.1 में दिए गए अनुसार निर्धारित पूर्व प्रावधानों को बनाये रखते हुए महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे बीओटी टर्मिनलों के दरमानों में अतिरिक्त प्रावधान निर्धारित किए हैं। महापत्तन न्यासों और महापत्तन न्यासों में परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के दरमानों में निर्धारित मौजूदा अतिरिक्त प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“9क. पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए पोत के वर्गीकरण की प्रणाली

- (i) भारतीय ध्वज वाला विदेशगामी पोत, जिसके पास सामान्य व्यापार लाइसेंस है, सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय पोत में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे पोत जो भारतीय पत्तन में उसकी प्रथम पत्तन आगमन पर सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित होता है, जब तक यह भारतीय तट पर नहीं पहुंचता है, किसी और सीमाशुल्क परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) विदेशी ध्वज वाला विदेशगामी पोत महानिदेशक नौवहन द्वारा जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय पोत के रूप में परिवर्तन कर सकता है।

9ख. रियायती तटीय दर तथा विदेशी दर पर पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड

- (i) ऐसे परिवर्तन के मामलों में लदान करने वाले पत्तन द्वारा पोत के तटीय सामग्रियों का लदान प्रारंभ करने के समय से तटीय दरें वसूल की जाएंगी।
- (ii) ऐसे परिवर्तन के मामले में तटीय दरें केवल तब तक प्रभार्य होंगी, जब तक पोत तटीय कार्गो का उतराई प्रचालन पूरा करता है, उसके तत्काल बाद विदेशगामी दरें उतराई पत्तन द्वारा वसूल की जाएंगी।
- (iii) महानिदेशक, नौवहन से प्राप्त तटीय लाइसेंस वाले नियत भारतीय तटीय पोतों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए अन्य दस्तावेज की अपेक्षा नहीं होगी।

10. रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रभारों (सीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड

- (i) ‘विश्वव्यापी तथा तटीय’ परिचालन के लिए जारी किए गए सामान्य ट्रेडिंग लाइसेंस वाले विदेशगामी भारतीय पोत प्रहस्तन प्रभारों (एचएससी) के मामले में अर्थात् जलयान से तट स्थानांतरण और निम्नलिखित परिदृश्य में घाटशुल्क सहित घाट से/को भंडारण यार्ड और विलोमतः तटीय दरें लागू की जाएंगी:
- (क) तटीय चालन में परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।
- (ख) तटीय चालन में अपरिवर्तित* परन्तु किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।

*केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड का परिपत्र सं. 15/2002-सी. दिनांक 25 फरवरी 2002 बिना किसी सीमाशुल्क परिवर्तन के भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोतों में एक भारतीय पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक तटीय कार्गो की ढुलाई की अनुमति देता है।

- (ii) जहाजरानी महानिदेशक द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट अवधि अथवा नौप्रस्थान के लिए लाइसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित विदेशी ध्वज वाले पोत के मामले में, किसी भारतीय पत्तन से लादा गया तथा किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित तटीय कार्गो/कंटेनर तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए लागू दर पर वसूल किया जाएगा।”

3. आईएनएसए ने अपने ई-मेल दिनांक 24 मई 2018 के कवर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समुद्री कार्गो मालसूची और पोतांतरण विनियमावली, 2018 पर जारी की गई अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 की प्रति अग्रेषित की थी।

4.1. उक्त अधिसूचना दिनांक 11 मई 2018 का खंड 2 (च) नियत विदेशी मार्ग के माध्यम से पोतांतरित तटीय माल परिभाषित करता है जोकि निम्नवत् है:-

“(च) “नियत विदेशी मार्ग के माध्यम से पोतांतरित तटीय माल” अर्थात्:

- (i) पूर्व तट पर एक भारतीय पत्तन और पश्चिमी तट पर दूसरे भारतीय पत्तन के बीच अथवा विलोमतः परिवहनित तटीय माल, श्रीलंका के क्षेत्रीय जलमार्गों के माध्यम से पोत द्वारा, बीच में श्रीलंका में किसी पत्तन पर आने वाले अथवा नहीं आने वाले और पोत बदले बिना;
- (ii) पूर्व तट पर एक भारतीय पत्तन और भारत में नदी पत्तन के बीच अथवा विलोमतः परिवहनित तटीय माल, बंगलादेशी जलमार्गों के माध्यम से गुजरने वाले मार्ग के माध्यम से पोत द्वारा, और पोत बदले बिना;”

4.2. उक्त अधिसूचना से संबंधित जो तटीय माल को श्रीलंका/बंगलादेश जलमार्गों में नियत विदेशी पत्तन के माध्यम से परिवहन किए जाने की अनुमति देता है जब कार्गो एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक ढोया जाता है, आईएनएसए ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या जलयान और कार्गो जो बंगलादेश अथवा श्रीलंका के क्षेत्रीय जलमार्गों के माध्यम से एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन जाएंगे तब भी परिवहन मार्ग की परवाह किए बिना पोत तथा कार्गो दोनों के लिए (रियायती) तटीय प्रशुल्क वसूल किया जाना जारी रहेगा।

4.3. सीबीआईटीसी की उक्त अधिसूचना 1 अगस्त 2018 से प्रभावी है।

5.1. मौजूदा निर्धारण और आईएनएसए द्वारा अंग्रेषित सीबीआईटीसी की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2018 का उल्लेख करते हुए, हमारे पत्र दिनांक 3 जुलाई 2018 और अनुस्मारक दिनांक 25 जुलाई 2018 द्वारा जहाजरानी महानिदेशालय से अनुरोध किया गया था कि कुछ बिन्दुओं पर हमें सलाह दें।

5.2. प्रतिसाद में, जहाजरानी महानिदेशालय ने अपने पत्र सं. डी-12/विविध(17)/14 दिनांक 7 अगस्त 2018 द्वारा अपना जवाब भेजा था। जहाजरानी महानिदेशालय से मांगी गई सलाह और उसपर जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा प्रेषित जवाब का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

क्र.सं.	जहाजरानी महानिदेशालय से मांगी गई सलाह	जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा प्रेषित जवाब
(i)	क्या नियत विदेशी मार्ग के माध्यम से एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक तटीय माल का परिवहन करने वाला पोत रियायती तटीय पोत संबंधित प्रभारों के लिए पात्र है।	वर्तमान में, रियायती प्रशुल्क सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोतों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए, यह कार्यालय मानता है कि दो भारतीय पत्तनों के बीच माल की ढुलाई में लगे भारतीय पोत रियायती प्रशुल्क के लिए पात्र रहने चाहिए भले ही उसने सीबीआईटीसी अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11-05-2018 के अनुसार विदेशी पत्तन को छुआ हो।
(ii)	क्या नियत विदेशी मार्ग के माध्यम से एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक पोतांतरित तटीय माल रियायती कार्गो संबंधित प्रभारों के लिए पात्र है।	जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्गो संबंधित प्रभार भी, तटीय पोतों के लिए यथा लागू रियायती दर पर वसूल किए जाएंगे, भले ही माल सीबीआईटीसी अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11-05-2018 के अनुसार विदेशी क्षेत्र के माध्यम से ढुलाई किया जाने वाला माल हो। रियायती प्रशुल्क की नीति कार्गो आवागमन के लिए वरीयता पसंद के रूप में दो भारतीय पत्तनों के बीच जलमार्ग के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। अतः, एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन ले जाये जाने वाले किसी माल को लदाई तथा उतराई के दोनों भारतीय पत्तनों द्वारा रियायती प्रशुल्क माना जाना चाहिए।
(iii)	क्या तटीय रियायती पोत संबंधित प्रभारों और रियायती कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों को पात्र बनाने के लिए ऐसे पोत हेतु कोई शर्त निर्धारित करनी होगी जब पोत पूर्व तट पर एक भारतीय पत्तन से पश्चिम तट पर दूसरे भारतीय पत्तन अथवा विलोमतः श्रीलंका के क्षेत्रीय जलमार्गों के माध्यम से जाता है, भले ही इस बीच श्रीलंका में किसी पत्तन पर आगमन होता है अथवा नहीं और पोत बदले बिना।	भारतीय तटीय पोत पहले से ही कुछ रियायती प्रशुल्क और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब तटीय पोतों को भी श्रीलंका पत्तन को छुते हुए अथवा बिना छुए बंगलादेश जलमार्गों और श्रीलंका के क्षेत्रीय जलमार्गों को छुने की अनुमति दी गई है। इसलिए, तटीय पोतों तक पहले से विस्तारित लाभों को ऐसे तटीय पोतों सहित सभी तटीय पोतों के लिए जारी रखने की अनुमति दिए जाने की जरूरत है जो बंगलादेश जलमार्गों और श्रीलंका के क्षेत्रीय जलमार्गों को छुते हैं, भले ही श्रीलंका के पत्तन को छुआ जाता है अथवा नहीं। सीबीआईटीसी अधिसूचना दिनांक 11-05-2018 की अपेक्षा को पूरा करने से इतर कोई और शर्त अधिरोपित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
(iv)	क्या तटीय रियायती पोत संबंधित प्रभारों और तटीय रियायती कार्गो संबंधित प्रभारों को पात्र बनाने के लिए ऐसे पोत हेतु कोई शर्त निर्धारित करनी होगी जब पोत पूर्व तट पर किसी भारतीय पत्तन और भारत में किसी नदी पत्तन के बीच अथवा विलोमतः बंगलादेश के जलमार्गों के माध्यम से गुजरने वाले मार्ग के माध्यम से जाता है, और पोत बदले बिना।	जैसाकि उपर्युक्त टिप्पणी में दिया गया है।

6. इस प्रकार, जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के अनुसार, पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभारों दोनों में रियायत सीबीआईटीसी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2018 के खंड 2(च) के अनुसार नियत विदेशी मार्ग अर्थात् (क) पूर्व तट पर एक भारतीय पत्तन और पश्चिमी तट पर दूसरे भारतीय पत्तन के बीच अथवा विलोमतः परिवहनित तटीय माल, श्रीलंका के क्षेत्रीय जलमार्गों के माध्यम से पोत द्वारा, बीच में श्रीलंका में किसी पत्तन पर आने वाले अथवा नहीं आने वाले और पोत बदले बिना और (ख) पूर्व तट पर एक भारतीय पत्तन और भारत में नदी पत्तन के बीच अथवा विलोमतः परिवहनित तटीय माल, बंगलादेशी जलमार्गों के माध्यम से गुजरने वाले मार्ग के माध्यम से पोत द्वारा, और पोत बदले बिना में परिवहनित पोत तथा तटीय माल के लिए लागू होगी।

जहाजरानी महानिदेशालय ने बताया है कि सीबीआईटीसी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2018 की अपेक्षा को पूरा करने से इतर कोई और शर्त निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी अस्पष्टता से बचने और सभी महापत्तनों और बीओटी परिचालकों में एकसमान रूप से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए, इस प्राधिकरण ने पाया कि जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर और सीबीआईटीसी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2018 के खंड 2(च) के अनुसार सभी महापत्तन न्यासों तथा वहां पर परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के मौजूदा दरमानों में प्रावधान निर्धारित करना उचित होगा। चूंकि यह मामला सीबीआईटीसी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2018 से आया है, इसलिए यह 2008 के अप्रकट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देशों और 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित बीओटी परिचालकों सहित सभी बीओटी परिचालकों पर लागू होगा। यह उल्लेखनीय है कि ये बीओटी परिचालक पहले से ही सरकारी की तटीय रियायत नीति द्वारा शासित हैं।

7.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के मौजूदा दरमानों में निम्नलिखित शर्तों को शामिल करना अनुमोदित किया गया है:

- (i) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार पूर्व तट पर किसी भारतीय पत्तन और पश्चिमी तट पर दूसरे भारतीय पत्तन के बीच अथवा विलोमतः परिवहनित तटीय माल, बीच में श्रीलंका में किसी पत्तन पर आगमन करते हैं अथवा नहीं और पोत को बदले बिना, पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभारों में रियायत के लिए पात्र होंगे।
- (ii) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार पूर्व तट पर किसी भारतीय पत्तन और भारत में नदी पत्तन पत्तन के बीच अथवा विलोमतः परिवहनित तटीय माल, बंगलादेशी जलमार्गों से गुजरने वाले मार्ग के माध्यम से और पोत बदले बिना, पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभारों में रियायत के लिए पात्र होंगे।
- (iii) उपर्युक्त निर्धारित प्रावधान आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 और संशोधन आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 10 जून 2016 में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होंगे।

7.2. सामान्यतः, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करें भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होती हैं। चूंकि सीबीआईटीसी की उक्त अधिसूचना 1 अगस्त 2018 से लागू है, इसलिए यह प्राधिकरण उपर्युक्त प्रावधान का कार्यान्वयन 1 अगस्त 2018 से अनुमोदित करता है।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा./242/18]

Tariff Authority for Major Ports NOTIFICATION

Mumbai, the, 25th September, 2018

No. TAMP/53/2015-VOCPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby passes a common Order as regards concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/53/2015-VOCPT

Indian National Shipowners' Association

- - - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 25th day of September 2018)

This matter deals with the concessional coastal tariff for vessels and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance brought out by Indian National Shipowners' Association (INSA) vide e-mail dated 24 May 2018.

2.1. In compliance of policy direction issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 vide its letter No.PR-14019/29/2001-PG dated 1 January 2005 and subsequent policy direction

dated 15 March 2005, coastal concessional vessel related charges and coastal concessional cargo/ container related charges were prescribed in the Scale of Rates of Major Port Trusts and BOT operators vide tariff Orders dated 7 January 2005 and 15 March 2005, as given below:

- "1 The vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels,*
- 2.1 The cargo/container related charges for all coastal cargo/containers, other than thermal coal and POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets, should not exceed 60% of the corresponding charges for normal cargo/container related charges.*
- 2.2 In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.*
- 2.3 In case of container related charges, the concession is applicable on composite box rate. Where itemized charges are levied, the concession will be on all the relevant charges for ship-shore transfer, and transfer from/to quay to/from storage yard as well as wharfage on cargo and containers.*
- 3 The charges for coastal cargo/containers/vessels shall be denominated and collected in Indian Rupee."*

2.2. Subsequently, while processing the clarification sought by V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) with reference to representation made by one of the BOT operators i.e. Dakshin Bharat Gateway Terminal Pvt. Ltd. (DBGTPL) operating at VOCPT and based on the communication received from DG Shipping vide their letter No.SD-12/Misc (17)/14 dated 13/17 August 2015, letter No.SD-12/Misc (17)/14 dated 19 November 2015 and letter No.SD-9/CHART(309)/2016 dated 20 May 2016 in the matter, this Authority vide its Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 and amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 10 June 2016, has prescribed additional provisions in the Scale of Rates of Major Port Trusts and the BOT Terminals operating thereat retaining the earlier provisions prescribed as brought out in para 2.1. above. The existing additional provisions prescribed in Scale of Rates of Major Port Trusts and BOT operators operating in Major Port Trusts are reproduced below:

“9A. System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC)

- (i) A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
- (ii) A Foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a License for Specified period or voyage issued by the Director General of Shipping and a custom conversion order.

9B. Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate

- (i) In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
- (ii) In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
- (iii). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.

10. Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate

- (i) Foreign going Indian Vessel having General Trading License issued for ‘worldwide and coastal’ operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:
 - (a). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

- (b). Not converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

* The Central Board of Excise and Customs Circular No.15/2002-Cus. dated 25 February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.

- (ii) In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a License for Specified period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/ container."

3. The INSA under cover of its e-mail dated 24 May 2018 has forwarded a copy of Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 on Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations, 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBITC), Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.

4.1. Clause 2(f) of the said Notification dated 11 May 2018 defines coastal goods transited through a designated foreign route as follows:

"(f) *"Coastal goods transited through a designated foreign route" means:*

- (i) *coastal goods transported between an Indian port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri Lanka, whether or not calling any port in Sri Lanka in between and without change of vessel;*
- (ii) *coastal goods transported between an Indian port on east coast and a river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel;"*

4.2. Referring to the said Notification that allows coastal goods to be transited through designated Foreign Port in Sri Lanka/ Bangladesh waters when carrying cargo from one Indian Port to another Indian Port, the INSA has sought clarification whether the ships and cargo that would move from one Indian Port to another Indian Port through territorial waters of Bangladesh or Sri Lanka would continue to be charged (concessional) coastal tariff both for vessel and cargo irrespective of transit route.

4.3. The said Notification of CBITC is effective from 1 August 2018.

5.1. Bringing out the existing prescription and referring to the Notification of CBITC dated 11 May 2018 forwarded by the INSA, the Directorate General of Shipping was vide our letter dated 3 July 2018 requested to advise us on a few points, followed by reminder dated 25 July 2018.

5.2. In response, the Directorate General of Shipping vide its letter No.D-12/Misc(17)/14 dated 7 August 2018 has furnished its reply. A summary of advice sought from Directorate General of Shipping and reply furnished by Directorate General of Shipping thereon is tabulated below:

Sl. No.	Advice sought from Directorate General of Shipping	Reply furnished by Directorate General of Shipping
(i)	Whether the vessel transporting coastal goods from one Indian Port to another Indian Port through a designated foreign route is eligible for concessional coastal vessel related charges.	At present Concessional tariff are prescribed for coastal cargoes/ containers/ vessels as per the policy directions of the Government. Therefore, this office considers that Indian vessels engaged in carriage of goods between two Indian ports should remain eligible for the concessional tariff even if it has touched a foreign port in terms of CBIC notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11.05.2018.
(ii)	Whether the coastal goods transited from one Indian Port to another Indian Port through a designated foreign route is eligible for concessional cargo related charges.	As mentioned above, the cargo related charges should also be charged at concessional rate, as applicable for coastal vessels, even if the goods are being carried over through a Foreign Territory in terms of CBIC notification No.38/2018-

		Customs (N.T.) dated 11.05.2018. The policy of concessional tariff will encourage use of water mode between two Indian ports as a preferable choice for cargo movement. Therefore, any goods moved from one Indian port to another Indian port should be treated with concessional tariff by both Indian ports of Loading and Discharging.
(iii)	Whether any conditions have to be prescribed for such vessel to become eligible for coastal concessional vessel related charges and concessional cargo/ container related charges when the vessel moves from one Indian Port on East coast and another Indian Port on West coast or vice versa through the territorial waters of Sri Lanka whether or not calling any Port in Sri Lanka in between and without change of vessel.	Indian coastal vessels are already enjoying certain concessional tariffs and benefits. Now the coastal vessels are also allowed to touch the Bangladesh waters and territorial waters of Sri Lanka with or without touching the Sri Lankan Port. Therefore, the benefits already extended to coastal vessels need to be continued to all coastal vessels including to coastal vessels which touch the Bangladesh waters and territorial waters of Sri Lanka whether touching the Sri Lankan Port or not. No further condition is required to be imposed other than meeting the requirement of the CBIC notification dated 11.05.2018.
(iv)	Whether any conditions have to be prescribed for such vessel to become eligible for coastal concessional vessel related charges and coastal concessional cargo related charges when the vessel moves between an Indian Port on East coast and a river Port in India or vice versa through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel.	Same as above comments.

6. Thus, as per clarification furnished by Directorate General of Shipping, concession in both vessel related charges and cargo related charges shall be applicable for vessel and coastal goods transported in designated foreign route in term of clause 2(f) of CBITC Notification dated

11 May 2018 i.e. (a). between an Indian Port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri Lanka, whether or not calling any port in Sri Lanka in between and without change of vessel and (b) coastal goods transported between an Indian port on east coast and a river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel.

The Directorate General of Shipping has stated that no further conditions need to be prescribed other than meeting the requirement of CBITC Notification dated 11 May 2018. To avoid any ambiguity and to ensure uniformity in application across all Major Port Trusts and BOT operators, this Authority finds it appropriate to prescribe provisions based on the clarification issued by DG Shipping and in line with the clause 2(f) of CBITC Notification dated 11 May 2018 in the existing Scale of Rates of all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat. Since the matter flows from the CBITC Notification dated 11 May 2018, it shall be applicable to all BOT operators, including BOT operators governed by Upfront tariff setting guidelines of 2008 and Reference tariff guidelines of 2013. It is noteworthy that these BOT operators are already governed by the coastal concession policy of the Government.

7.1. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, insertion of the following conditionalities in the existing Scale of Rates of all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat are approved:

- (i) Coastal goods transported between an Indian port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri Lanka, whether or not calling any port in Sri Lanka in between and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (ii) Coastal goods transported between an Indian port on east coast and a river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel in

terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.

- (iii) The provisions prescribed above shall be subject to adherence to the provisions prescribed in the Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 and amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 10 June 2016.

7.2. Ordinarily, the rates approved by this Authority come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. Since the said Notification of CBITC is effective from 1 August 2018, this Authority approves the implementation of the above provisions with effect from 1 August 2018.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-.III/4/Exty./242/18]